सवाल पूछना चाहता हूं कि उधर की जनता और उधर के जनप्रतिनिधि चार दिन किधर से दिल्ली आयेंगे, वे इसकी भी व्यवस्था बताये कि आजमगढ़ में जनप्रतिनिधियों कि संख्या ज्यादा है और आजमगढ़ जनपद एक कमिश्रिरी है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए इसको प्रमुख नगरों से जैसे कलकत्ता से, मुम्बई से, मद्रास से संबंध करने की क्या कोई योजना बनाई है? अगर योजना बनाई है तो वह कितने दिन में क्रियान्वित होगी और अगर नही बनाई है तो क्यों नही बनाई है?

**श्री राम विलास पासवान**: उपसभपति जी, मैंने कहा कि मऊ-शाहगंज के रास्ते से सिर्फ एक गाडी चल रही है । लेकिन उसके अलग-बगल में गोरखपुर है, वाराणसी है वहां से हो लिंक लाइन है उससे 9 गाडियां दिल्ली के लिए चल रही है । जहां तक उनका दूसरा सवाल है, उसके सबंध में मैंने पहले ही जवाब दे दिया है ।

**देश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)**

*143.**डा. महेश चन्द्र शर्मा**: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम देश में राज्य-वार कौन-कौन से जिलों में चल रहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक ने यह कार्यक्रम भारत को दिया है या सरकार ने इसे विश्व बैंक से मांगा है;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(घ) इस संदर्भ में विश्व बैंक कितना राशि खर्च करने वाला है और क्या उक्त राशि अनुदान के रूप में होगी अथवा ऋण के रूप में होगी;

(ङ) क्या विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम के लिए कोई शर्त लगायी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री एस.आर. बोम्मई)** : (क) से (च) एक विवरण सभा पतल पर दिया गया है ।

**विवरण**

(क) से (च) प्रांरभिक शिक्षा के सर्वसुभीकरण को मूर्त रूप देने सबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1992 में यथा संशोधित) के लक्ष्य को ध्यान में रखकर 1994 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया । कार्यक्रम के लिय विदेशी वित्त पोषण विकासशील देशों में सभी के लिए शिक्षा परियोजनाओं की मदद करने संबंधी जोमतियन सम्मेलन में अंतराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई प्रतिबद्धता तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) द्वारा यह सहायता प्राप्त करने के सबंध में निर्धारित किए गए दिशा निर्देशो के अनुरूप है ।

विश्व बैंक डी.पी.ई.पी. चरण-। के लिए 260.3 मिलियब अमरीकी डालर की सहायता दे रहा है जिसके अंतर्गत 7 वर्ष की अवधि में असम, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 23 जिले शामिल होगे तथा डी.पी.ई.पी. चरण-॥ के तहत 11 राज्यों नामतः असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उडीसा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कनार्टक, तमिलनाडऊ और केरल में 70 जिलों के लिए 450.8 मिलियन अमरीकी डालर (सह वित्त पोषण व्यवस्था के तहत 425 मिलियन अमरीकी डालर की आई.डी.ए. क्रेडीट तथा 25.8 मिलियन अमरीकी डालर का नीदर्लैंड सरकार से अनुदान) की राशि सहायता के रूप में दे रहा है । जिन जिलों का विश्व बैंक की सहायता प्राप्त हो रही है उनके नाम विवरण। में दिए गए है (नीचे देखिए)

विश्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता मानव, शर्तो और विनियमों पर अंर्तराष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.) से आसान ऋण के रूप में है । क्रेडिट समझौता के तहत, कार्यक्रम के चरण । और ॥ में संबंधित राज्य सरकारों कों प्रारंभिक शिक्षा पर व्यव को वास्तविक रूप से क्रमशः 1991-92 तथा 1995-96 के स्तरो पर रखन होगा ।

**विवरण-।**
**राज्यों/जिलों की सूची**

| क्र.स. | राज्य का नाम | | शामिल किए गए जिले |
|---|---|---|---|
| | | **डी.पी.ई.पी. चरण-।** | **डी.पी.ई.पी. चरण-।।** |
| 1. | असम | ध्रुवी, दारंग़, कार्वी आगलोग, मोरीगांव | बरपेटा, बोगाईगांव, गोलपाड़ा कोक्ड़ाझाड़, सोनितपुर |
| 2. | हरियाणा | कैथल, जींद, हिसार, सिरसा, | भिवानी, गुड़गाव,मोहिदरगढ़ |
| 3. | कर्नाटक | रायचूर, मंड़या, कोलर, बेलगाम | बंगलौर देहात, गुलवर्ग, मैसूर, बिदर, बेल्लारी, खिजापुर, धारवाड़ |
| 4. | केरल | कसारगोड़े, व्यानाड, मल्लापुरम | इदुकी, पालका, तिरूवनंतपुरम |
| 5. | तमिलनाडु | धरमपुरी, तिरूव-अन्नामलाई,सुंबुवरयार, दक्षिण, आरकोट | पेंरबदूर, रामनाथपुरम, पुदुकोटाइ |
| 6. | महाराष्ट्र | परभनी,नांदेड,उस्मानाबाद, औरंगाबाद,लातूर | बाड, धूले, गडचिरौली, जालना |
| 7. | मध्य प्रदेश | | भींड, मुरैंना, सियोनी, मंडल्ल, शिवपुरी, झबुआ, बस्तर, शाहजहांपुर, खारगोना, दतिया, देवास विदिशा, दामोह, रायपुर, खांडवा |
| 8. | | | संबलपुर, खैरागढ, क्योंझर, बोलनगीर, धेनकनाल,गजपति, कालाहांडी, रायगढ |
| 9. | उत्तर प्रदेश | | महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बदायू, खीरी, ललितपुर, पिलीभीत, बस्ती, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, सोनाभद्र, देवादि, हरदोई, बरली, फिरोजाबाद |
| 10. | हिमाचल प्रदेश | | सिरमौर, लाहुल-स्फीति, चम्बा, कुल्लू |
| 11. | गुजरात | | बनासकंठा, पंचमहल, और बंगल |

**डा. महेश चन्द्र शर्मा**: उपसभापति महोदया, मै आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश को विदेशों में से कही से भी ऋण मिले तो हमारी सरकारें तुरन्त लेने पहुंच जाती है। ये जो शिक्षा को सुदूर तक पहुंचाने के लिए विश्व बैंक से ऋण आ रहा है, यह लगभग एक अरब 16 करोड 20 लाख अमेरिकन डालर है। महोदया, मै यह जानना चाहुंगा कि तीन साल हो गए हो गए इस प्रकल्प को लागू हुए क्या तीन साल में इसकी कोई समीक्षा हुई है और जो इसका समीक्षा तंत्र है उसके बारे में क्या मंत्री महोदय सदन में कुछ बतायेगे?

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, World Bank assistance is to the tun of Rs. 2300 crores, to be precise. I have given the names of districts and states which have been benefited. There is a monitoring agency which evaluates it at the state level and the district level. The number of additional schools that are opened and the number of additional teachers that are appointed, all these things are monitored every year.

**डा. महेश चन्द्र शर्मा**: मैडम, मैंने कहा है कि क्या यह समीक्षाआ प्रतिवेदन को सदन में रखेगे? क्योंकि तीन साल हो गए इसकी अभी तक समीक्षा नही आई है। दूसरे रूप में, मै यह जानना चाहुंगा वह जो राशि वापस की जाएगी तो क्या इसको केवल सरकार वापस

करेगी या राज्य सरकारें भी मिलकर वापस करेंगी और इसका ब्याज कितना होगा?

SHRI S.R. BOMMAI: Madam, it will be paid by the Central Government only. The government of India has to pay the World Bank loan. The service charge is at the rate of three-fourth of one per cent per annum on the principal amount of credit withdrawn and outstanding and the committed charge on the amount not withdrawn is at a rate not exceeding half on one per cent per annum. The repayment period is 35 years which can be extended by ten years. That means, you have to pay it within 45 years with minimum of interest and this will be paid entirely by the Government of India.

**डा. महेश चन्द्र शर्मा**: ब्याज कितना है? ब्याज की दर क्या है?

SHRI S. R. BOMMAI: Half a per cent.

**डा. महेश चन्द्र शर्मा**: समीक्षा की रिपोर्ट...

**उपसभापति**: 12 बजे गए है । Quesiton Hour is over.

## WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

वडोदरा डिवीजन में आमान परिवर्तन

*145. **श्री गोपालसिंह जी सोलंकी**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेलवे के अंतर्गत वडोदरा डिविजन की मीटर रोज लाइन को बडी लाइन में बदलने हेतु आमान परिवर्तन कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) क्या इस संबध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या वडोदरा विभागीय प्रबंधक ने कोई विस्तृत रारूप प्रस्तुत किया है;

(ङ) क्या वक्त आमान परिवर्तन कार्यक्रम हेतु धनराशि निर्धारित की गयी है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(छ) कितनी मीटर गेज लाइन को आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान बदला नही गया है?

**रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान)**: (क) से (ग) पश्चिम रेलवे के वदोदरा मंडल में एक छोटी साल्ट साइडिंग ध्रांगध्रा-कुडा (22 कि.मी) और कुछ छोटी लाइनों के अलावा कोई मीटर लाइन नही है । मीटर लाइन की इस साल्ट साइडिंग के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है और इस कार्य को 1997-98 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है । भरूच-सामनी-जस्बूसर-विश्वामित्री (95.54 कि.मी.), सामनी-दाहेज (40 कि.मी.), जस्बूसर-कावी (26 कि.मी.) भादरण बोचारण-पेटलाद-नडियाद (59 कि.मी.) , रानू पिपरी-भादरण (26 कि.मी) तथा मियागंज-करजन डभोई-साबरिया (80 कि.मी) छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण कर लिए गए है और ये विरार और अहम्दाबाद के बीच तीसरी लाइन परियोजना, जो इस मंत्रालय के विचाराधीन है, के सर्वेक्षण का एक भाग है ।

(घ) इस संबंध में मंडल रेल प्रबधक/वडोदरा द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नही है ।

(ङ) और (च) अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इसमें से किसी भी लाइन पर कार्य शुरू होने पर इस मंडल की मौजूदा मीटर लाइनों/छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए धनराशि निर्धारित की जाएगी ।

(छ) 22 कि.मी लम्बी ध्रांगध्रा-कुडा साल्ट साइडिंग के आमान परिवर्तन का कार्य 1997-98 के पूरक बजट में शामिल कर लिया गया है ।

**Forest Policy**

*46. SHRI J AY ANT KUMAR MALHOUTRA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the current forest policy in order to ensure more involvement of local communities in guarding and managing forests;

(b) if so, the details thereof; and

(c) Government's stand on World Forest Treaty?